MR. DEPUTY-SPEAKER : Now it is all settled. Why do you want to take it up?

Now, I shall put Supplementary Demands for Grants (Railways) 1982-83 to vote.

The question is :

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India *to defray* the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1983, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof—

Demand Nos. 2 and 16.

The motion was adopted

APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 3 BILL*, 1982

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI P. C. SETHI) : I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1982-83 for the purposes of Railways.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1982-83 for the purposes of Railways."

The motion was adopted.

SHRI P. C. SETHI : Sir, I introduce the Bill.

I beg to move †:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1982-83 for the purposes of Railways, be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1982-83 for the purposes of Railways, be taken into consideration."

SHRI SUDHIR GIRI (Contai) : Speaking on my cut motion, I would like to say that my constituency is lying in a very backward region of West Bengal. Rail communication in this region is nil. Thousands of people of this region have to travel daily a long distance by bus and truck to reach Calcutta, Haldia and other trade centres to transact their daily business. If this long distance is covered by railways, apart from a great deal of revenue to the railways, the travelling public would be greatly benefited. For this purpose, a rail link between Tamluk and Digha in the district of Midnapur is urgently needed.

In 1980-81 a provision of Rs. 20,000 was made for a preliminary survey of the viability of the rail link between Tamluk and Digha. In answer to my oral question the hon. Minister, Shri Mallikarjun, stated on the floor of the House that from the view point of the passengers the prospect of the proposed rail link is very good. To a subsequent question in this regard, it was mentioned in a written reply that the Planning Commission has not provided any amount of money for this rail link.

I may state here that Contai Taluk, my constituency, being by the Bay of Bengal, thousands of tonnes of dried fish are transported from there to cater to the needs of different parts of the country. Further, there are many salt factories in the region, producing thousands of tonnes of salt, which is also transported to different regions of the country. Betel leaves constitute one of the principal economic crops of the region. These are also transported to different parts of the country. Transport of all these items by truck, besides being costly, is also time-consuming.

---

*Published in Gazette of India Extraordinary Part II, Section 2, dated 2-8-1982.

†Introduced/moved with the recommendations of the President.

The region to be covered by the proposed rail link, between Tamluk and Digha, is inhabited by nearly 15 lakhs of people. At present, the requirements of these people of consumer goods such as foodgrains, cement, building materials, cloth, oil etc. are transported by motor vehicles and country boats, which cause much inconvenience and suffering in terms of higher transport cost.

Furthermore, Digha is a sea resort, which attracts tourists in thousands. The only communication at present is motor vehicles. Naturally, this causes inconvenience to the tourists, as much time is consumed in transport. Taking all these factors into consideration, I would appeal to the Minister to arrange for the construction of a rail link between Digha and Tamluk at an early date.

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नार्थ ईस्ट (पूर्वोत्तर) रेलवे की दुर्दशा के सम्बन्ध में थोड़ा-बहुत कहना चाहता हूं। अभी मैं कल दिल्ली से जयपुर गया था, यह भी मीटर गेज लाइन ही है और एन० ई० रेलवे भी मीटर गेज है, यदि कोई इन दोनों लाइनों पर सफर कर चुका हो तो वह यही समझेगा कि पूर्वोत्तर रेलवे अब वाइन्ड-अप होने वाली है। जो भी इंजन चलते हैं वह कहीं भी रास्ते में रुक जाते हैं। इक्वीपमेन्टस के रखरखाव की स्थिति यहां तक खराब हो चुकी है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करता हू कि वे इस पर ध्यान दें और इस स्थिति में सुधार के उपाय करें।

दूसरी बात यह है कि पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर स्टेशन को जो सुविधायें पहले प्राप्त थीं वह भी हाल में वापिस ले ली गई हैं। 1975 में समस्तीपुर-हावड़ा के बीच तीन-तीन गाडियां थीं लेकिन आज एक भी नहीं है। जबकि आप दूसरे क्षेत्रों में सुविधायें बढ़ा रहे हैं, समस्तीपुर में जो सुविधायें पहले से मौजूद थीं, उनको भी आप वापिस ले रहे हैं। यदि आप उन गाड़ियों की हालत पर नजर दौड़ायें जो हावड़ा से समस्तीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर और गोरखपुर तक जाती हैं तब आप राजी हो जायेंगे कि वहां पर और ट्रेन्स की आवश्यकता है। कानपुर से समस्तीपुर तक एक गाड़ी चलती हैं। पिछले रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि दिल्ली तक रोजाना रेल सेवा प्रारम्भ कर दी जाएगी। मेरा आग्रह है कि कानपुर से समस्तीपुर जो गाड़ी जाती है, उसको दिल्ली तक लायें।

तीसरी बात, दरभंगा समस्तीपुर परिवर्तित योजना जो बनी थी, उसमें बाद के दिनों में 1980-81 में 15 लाख रुपए की राशि रखी गई थी। उसका उद्घाटन भी तत्कालीन रेल मंत्री, श्री केदार पांडे जी, कर चुके हैं। 1981-82 में इस योजना के तहत खर्च के लिए 50 लाख रुपए की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब उसे वापिस ले लिया गया है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप उस पर ध्यान दें और जो जीवनोपयोगी योजनायें हैं, उनको फिर से कार्यान्वित कर दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान रेल की लाइनों के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कम से कम एक अलग जोन की इसके लिए व्यवस्था करवा दीजिए। इस संबंध में रेल मंत्री जी को हम बराबर कहते आ रहे हैं और बराबर कहते हैं कि इस की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक राजस्थान में एक अलग रेल जोन नहीं बनेगा तब तक वहां का डवेलपमेंट नहीं हो सकता है। इस संबंध में हमारी मांग है, आप भी सिफारिश करा दीजिए कि वहां पर एक अलग जोन बनाया जाए, ताकि वहां का डवेलपमेंट हो। राजस्थान एक डेजर्ट इलाका है, सब से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सबसे बैकवर्ड है, यदि वहां का विकास करना है तो निश्चित तरीके से वहां अलग जोन की व्यवस्था करनी चाहिए।

हमारे यहा पर एक सर्वे लाइन थी। इस बारे में कन्सलटेटिव कमेटी में कहा और चिट्ठी भी लिखी। जवाब दिया गया कि सर्वे हो जाएगा। कोटा से देवगढ़ तक ब्राड-गेज लाइन के सर्वे के लिए बजट भाषण में स्वीकृति दी गई है। टोडारायसिंह से नाथ-द्वारा तक के लिए भी सैंक्शन किया है। पिछले दो तीन सालों में श्री कमलापति त्रिपाठी जी रेल मंत्री थे, उसके बाद श्री केदार पांडे जी रेल मंत्री बने और अब श्री सेठी जी रेल मंत्री

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

हैं—तीनों रेल मंत्रियों ने इसको बजट में स्वीकृति दी लेकिन आज तक भी सर्वे नहीं हुआ है। पता नहीं इस संबंध में कब तक कार्यवाही होगी और कब लाइन बनेगी। हम लोगों की पांच साल की अवधि है। पांच साल बराबर इसके लिए हम चिल्लाते रहेंगे, लेकिन इस संबंध में कोई काम नहीं किया जाएगा। आपका रेलवे बोर्ड भी पता नहीं किस प्रकार काम करता है। जब भी कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है, तो कह दिया जाता है कि हो जाएगा। वही स्टीरियो-टाइप जवाब दस साल पहले का रेलवे बोर्ड द्वारा दे दिया जाता है। इसके सिवाय और कुछ नहीं करता। मैं चाहता हूं कि इसका सर्वे तुरन्त होना चाहिए और अगर यह लाइन बन सकती है तो उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। प्लानिंग मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, इस पिछड़े हुए क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सिफारिश कीजिए ताकि राजस्थान का कुछ विकास हो सके।

MR. DEPUT8Y-SPEAKER : Speak to the Minister separately and get the things done.

श्री गिरधारी लाल व्यास : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मीनाक्षी एक्सप्रेस जो कि दो दिन चलती है उसको सात दिन चलाइए, क्योंकि लोगों को बहुत तकलीफ है। दूसरे चेतक को आपने जल्दी लाने का आश्वासन दिया है, पार्लियामेंट के अन्दर, उसको जल्दी लाने की कोशिश कीजिए। इस गाड़ी में आप डीजल का इंजन लगाइए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can write a letter to the Minister. How do you speak all these things through the Parliament ? You can discuss only some points at issue.

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन इस संदर्भ में कोई जवाब नहीं मिलता है। कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सिफारिश करें कि वे इस संबंध में कुछ व्यवस्था करें।

भीलवाड़ा स्टेशन के लिये भी मैंने पहले भी कहा था, उस को माडर्नाइज कराइये। अजमेर-खंडवा लाइन बहुत पुरानी है, उस के ट्रैक्स टूटे हुए हैं जिस से बहुत ज्यादा एक्सीडेन्ट्स होते हैं। उस के कोचेज और वेगन्स सब पुराने और टूटे-फूटे हैं। गाड़ियों में पानी और दूसरी सुविधाओं का अभाव है। आप ने 700 करोड़ रुपया कलकत्ता को दे दिया और हमारी लाइनें टूटी पड़ी रहीं—यह आप का क्या न्याय है? आप की इस बात को यहां पर कोई भी पसन्द नहीं करता। 50 साल तक भी वह अण्डरग्राउण्ड लाइन नहीं बनेगी, लेकिन हम पैसे के अभाव में तड़पते रहेंगे। इस लिये हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी तरफ भी तवज्जह दीजिये। इन को तो उस बात की कोई परवाह नहीं है, ये बड़े लोग हैं, लेकिन हमारी तरफ ध्यान देने से हमारा बेकवर्ड क्षेत्र आगे बढ़ेगा, जिससे हम को ही नहीं देश को भी फायदा होगा।

अब मैं एक-दो प्वाइन्ट्स और कहना चाहता हूं—दिल्ली से अहमदाबाद को बड़ी लाइन में कन्वर्ट करने की चर्चा बराबर चल रही है। प्लानिंग मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हुए हैं। यह सब से पुरानी लाइन है—इस के बड़ी लाइन में बदले जाने से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र—पांच राज्यों को फायदा होगा। इस लिये मेरा अनुरोध है कि इस को जल्द से जल्द बड़ी लाइन में बदलिये ताकि इन क्षेत्रों का विकास हो सके।

एक ट्रेन—गरीब नवाज एक्सप्रेस—आप ने आगरा से जयपुर के लिये चलाई है, उस को अजमेर तक ले जाइये ताकि अजमेर जाने वाले लोगों को उस का लाभ मिल सके।

इन शब्दों के साथ माननीय सेठी साहब ने जो बजट रखा है उस का समर्थन करता हूं। हमारा अनुरोध है कि हमारी बातों पर ध्यान दे कर उन को पूरा कराने की कृपा करें।

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri) : I am thankful to you for giving me this opportunity to express my views. I promise you that I would not take more than five minutes.

MR. SPEAKER : No, no.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : I want to invite the attention of the hon. Minister for Railways to only one point. I was listening to his speech very carefully and he said, "I am thinking of taking new projects but for want of funds I am unable to do it." But I would like to invite his attention to one project—the dream of

people of Konkon in Maharashtra i.e. West Coast Railway line which is popularly known as Konkon Railway line. When Prof. Madhu Dandavate was the Railway Minister during Janata regime, he pushed through this particular project. But I find that the construction is being made only from Bombay to Roha. People from two districts which I represent—Raigarh and Ratnagiri—and Sindhudurg which Prof. Dandavate represents, more than 70%, have not seen the railway. Does it look nice? We are coming at the end of the 20th Century and people have not seen the Railways! Konkon is a narrow strip. On one side there is Sindhu Sagar and on the other side is Sahyadri Mountain. It is very important from the point of view of defence because defence experts have said that when we have long coastline, it is absolutely necessary to have a parallel railway line. Taking into consideration all these fact I will appeal and request him to assist us to fulfil our dreams or at least tell us what steps you have taken. If you have not taken any steps what steps do you propose to take? Is it possible at least in my life to get an opportunity to travel from my place to Bombay? I hope Shri Sethi will assist me.

MR. DEPUTY-SPEAKER As a member of Parliament.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Even as a Member of Parliament or otherwise, I have nothing to say. But at least try hard to help us in getting a railway line and assist to fulfil the dream of people of years living in this strip of Konkon.

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सम्मान के साथ इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इन के भूतपूर्व मंत्री श्री केदार पांडे जी ने पब्लिक में और पार्लियामेन्ट में कहा था मुजफ्फर-पुर-नरकटियागंज लाइन को रक्सौल तक बड़ी लाइन में बनायेंगे। मैं चाहता हूं कि कि मंत्री महोदय साफ़-साफ़ बतलायें कि मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज लाइन कब तक बनने जा रही है या नहीं बनने जा रही है।

इसी के साथ में यह भी कहूंगा कि मेरे यहाँ एक बहुत ही नेग्लैक्टेड स्थान है जहां [illegible] लाइन की [illegible] है। मैं चाहता हूं कि हाजीपुर-लालगंज-वैशाली-साहबगंज-केसरिया-पहाड़पुर-हरसिद्धि हो कर सुगौली में जा कर मिले। यह गंडक कमांड एरिया में पड़ता है और वहां के विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस का सर्वेक्षण आप कराएं और इस में देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस से वैशाली को जोड़ा जा सकेगा जोकि पुराने जमाने में एक ऐतिहासिक महत्व रखता था और राजधानी रह चुका है। यह पर्यटन, व्यवसाय और तीर्थ-स्थलों को जोड़ने के लिए बहुत आवश्यक है और पिछड़े इलाकों के विकास के लिए भी इस लाइन का बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी मांग है कि इस का सर्वेक्षण जल्द से जल्द कराया जाए और मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज और रक्सौल तक एक बड़ी लाइन बनाई जाए। आप [illegible] प्रेडिसेसर का यह वायदा है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Hon. Member, everybody wants to speak. As a matter of fact, this is a wrong precedent which I have done because so many people wanted to speak. This should not have been a precedent. Shri Somnath Chatterjee also knows that.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You should have given in writing to participate in the Appropriation (Railways) Bill.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : Then, all right. write your points to the Minister. He will reply to it. All of you write your points to the Minister.

Now, the Railway Minister will reply.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : I am not calling you. Write your points to the Minister. As a special case, in the Appropriation Bill discussion, I have permitted and this should never be quoted as a precedent. Now the Railway Minister will reply.

(Interruptions)

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI P. C. SETHI): I have already replied to the points raised by the hon. Members.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1982-83 for the purposes of Railways, be taken into consideration."

The motion was adopted

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, we shall take up clause-by-clause consideration. The question is :

"That Clauses 2 and 3 and the Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

SHRI P. C. SETHI : Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

SUPPLEMENTARY-DEMANDS* FOR GRANTS (GENERAL), 1982-83

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, we go to the General Discussion and voting on Supplementary Demands for Grants (General) for which time allotted is 2 hours. This Bill has also got to be completed today.

Motion moved :

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of Consolidated Fund of India *to defray* the charges that will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1983, in respect of the following demands entered in the second column thereof—

Demand Nos. 12, 13, 26. 30, 42, 52, 63, 78, 79 and 100."

*Moved with the recommendation of the President.

Supplementary Demand for Grants (General) for 1982-83 submitted to the Vote of the Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant submitted to the Vote of the House	
1	2	3	
		Revenue Rs.	Capital Rs.
	MINISTRY OF COMMERCE		
12	—Foreign Trade and Export Production	—	480,00,00,000
13	—Textile, Handloom and Handicrafts	-	11,70,00,000
	MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE		
26	—Education	—	1,60,90,000
	MINISTRY OF ENERGY		
30	—Department of Power	1,000	7,00,00,000
	MINISTRY OF FINANCE		
42	—Other Expenditure of the Ministry of Finance	1,000	
	MINISTRY OF HOME AFFAIRS		
52	—Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	5,83,000	-
	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING		
63	—Broadcasting	—	1,000
	MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT		
78	—Ports, Lighthouses and Shipping	2,50,00,000	1,000
79	—Road and Inland Water Transport	—	8,00,00,000
	DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT		
100	—Department of Ocean Development	5,99,00,000	—

MR. DEPUTY SPEAKAR : Notices of cut motions—Shri T. R. Shamanna not present.